PUNE RESEARCH TIMES ISSN 2456-0960
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES VOL 4, ISSUE 4

भारत में गरीबी रेखा के अनुसार वर्तमान स्थिती का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. आर. एच. नगरकर
सहयोगी प्राध्यापक
जी. एस. कॉलेज ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स
नागपूर (महाराष्ट्र) भारत

देश में अनेक प्रयत्नों के बावजूद गरीबी विद्यमान है । गरीबी को गरीबी रेखा की सीमा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगो को अत्यंत गरीब माना गया है । गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते है । जिसमें कम आमदनी के कारण व्यक्ति अपनी अर्थिक जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है । विश्व बॅक के अनुसार ३२.७१ प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते है, सरकार की और से योजना (नीति) आयोग द्वारा गरीबी रेखा को परिभाषित किया जाता है । इसके लिए विभिन्न समयों में अलग अलग समितियों का गठन किया है । १) निरपेक्ष गरीबी २) सापेक्ष गरीबी. भारत में सबसे गरीबी राज्य उडीसा है । सरकारी प्रयत्नों के कारण गरीबी कम हुई है और दावा यह है कि वर्ष २००५–२००६ से २०१५–२०१६ इस दशक में २७१ मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले है । किंतू अभी और अधिक गंभीर प्रयत्नों की आवश्यकता है ।

मूल शब्द : गरीबी रेखा, सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, गरीबी उन्मूलन, कैलोरी, आय.

प्रस्तावना :—

गरीबी रेखा या निर्धारण रेखा आय के उस स्तर को कहते है जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी आर्थिक जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है । गरीबी रेखा अलग – अलग देश में अलग–अलग होती है । उदाहरण के लिए अमेरिका में गरीबी रेखा भारत में मान्य गरीबी रेखा से कॉफी ऊपर है । गरीबी है एक उचित रहवास का अभाव, गरीबी है बीमार होने पर, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाना, गरीबी है विद्यालय न जाना और पोषण तत्वों का अभाव है गरीबी ! सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनैतिक व्यवस्था में प्रतिनिधीत्व न होना और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार तैयार करते है ।

मूलत: सामाजिक और राजनैतिक असमानता आर्थिक असमानता का कारण बनती है । विकलांग और शरिरीक रुप से विकलांग व्यक्तियों के सामने सदैव दोहरा संकट बना रहता है । जहॉ एक और वे शारीरिक रुप से विकलांग होते है वही दूसरी और आजीविका का साधन नही मिलता, इसी प्रकार यह लोग भी गरीबी सीमा के नीचे चले जाते है । अगर किसी व्यक्ति को आय राष्ट्रीय औसत आय (National Avg. Income) के ६० प्रतिशत से कम है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवाला व्यक्ति मान लेते है । औसर आय का आकलन विभिन्न तरीको से किया जा सकता है ।

उदाहरण के लिए माध्य निकालने का तरीका, यानी १०१ लोगो में ५१ वा व्यक्ति यानी एक अरब लोगों में ५० करोडवे क्रम वाले व्यक्ति की आय को औसत आय माना जा सकता है । परिभाषा के आधार पर देखे तो माध्य के आधार पर तय गरीबी रेखा के आधार पर जो गरीब आबादी निकलेगी वह कुल आबादी के ५० फिसदी से कम रहेगी ।

अध्ययन का उद्देश :—

१) भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का अध्ययन करना ।

२) गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करेवाली जनसंख्या का अवलोकन करना ।

३) वर्तमान समय में गरीबी की रेखा का अध्ययन करना ।

संशोधन पत्र का प्रकार :—

इस संशोधन पत्र का प्रकार वर्णनात्मक है जिसमें समस्या से संबंधित विश्लेषण किया गया है

तथ्य संकलन के स्त्रोत :–

प्रस्तुत अध्ययन के लिए द्वितीयक स्त्रोत से तथ्य तथा जानकारी एकत्रित की गयी है । इसके लिए पत्रिकाओं, समाचार पत्र, इंटरनेट पर उपलब्ध सरकारी रिपोर्ट्स का उपयोग किया गया है ।

व्याप्ति :–

प्रस्तुत अध्ययन में संपूर्ण भारत में गरीबी की रेखा के निर्धारण और इसके नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या का अध्ययन किया गया है ।

सीमाएँ :–

भारत में गरीबी एक विकराल और भयावह सहै संपूर्ण गरीबी की समस्यॉ का अध्ययन नही करके निर्धारित की गयी गरीबी रेखा को केन्द्र मानकर अध्ययन को सीमित किया गया है । अध्ययन के लिए केवल द्वितीयक तथ्य और जानकारी का उपयोग किया गया है ।

विश्लेषण एवं निर्वचन :–

भारत में गरीबी बहुत व्यापक है किन्तु बहुत तेजी से कम हो रही है । अनुमान है कि विश्व की सम्पूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है । वर्ष २०१० में विश्व बॅक ने सूचना दी कि भारत के ३२.७ प्रतिशत लोग रोजाना की १.२५ की अंतराष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहते है और ६८.७ प्रतिशत लोग रोजाना की २ से कम में गुजारा करते है ।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २००६ से २०१६ के बीच २७.१० करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले है, फिर भी आज ३७ करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे है ।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २००५–२००६ में भारत के करीब ६४ करोड लोग (५५.१ प्रतिशत) गरीब थे, यह संख्या घटकर २०१५–१६ में ३६.९ करोड (२७.९ प्रतिशत) पर आ गयी । (Globle financial servie company credit Suisse) के अनुसार भारत एक बहुत व्यापक तौर पर गरीब मुलक है । साल २०१६ मे (MPI Index) यानी Multidimensional Poverty Index के मुताबिक भारत में

लगभग ३६.४० करोड लोग गरीब थे इस Index में गरीबी को स्वास्थ्य और रहन–सहन के १० मानको पर मापा जा सकता है । अगर कोई ३३ प्रतिशत मानको पर भी खरा नही उतर पाता तो उन्हे MPI गरीब माना जाता है ।

भारत में अनेक अर्थशास्त्रीयों एवं संस्थानों बनाए । इन सभी अध्ययनों का आधार कैलोरी को बनाया गया है । योजना आयोग (वर्तमान निति आयोग) द्वारा गठित विशेष दल की रिपोर्ट के अनुसार – ''ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति २४०० कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति २१०० कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से जिन्हे प्राप्त नही हो पाता उसे गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है ।

गरीबी को दो तरह से देखा जाता है :–

१) निरपेक्ष गरीबी २) सापेक्ष गरीबी

१) निरपेक्ष गरीबी :–

''एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से अर्थ है कि उसकी आय या उपयोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण के स्तर के नीचे स्तर पर रह रहा है ।'' दूसरे शब्दों में कहे तो ''गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम आय से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू आवश्यक होती है तथा जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ होता है ।''

२) सापेक्ष गरीबी :–

''सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है इस संबन्ध में विभिन्न वर्गो या देशों के निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है ।'' जिस वर्ग या देश के लोगो का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है वे उच्च निर्वाह स्तर या प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तूलना में गरीब मान जाते है, निर्वाह स्तर को आय एवं उपभोग व्यय के आधार पर माना जाता है ।

सुरेश तेंदूलकर समिती (२००९) ने प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग्य व्यय को आधार बनाया । समिती ने शहरी क्षेत्र में १००० रु प्रति व्यक्ति प्रति माह (३३ रुपये प्रति दिन) और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ८१६ रुपये प्रति महा (२७ रुपये प्रति दिन) से कम खर्च करनेवाले लोगो की गरीब बताया । इस समिती ने शहरी क्षेत्र में

१४०७ रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह (४७ रु. प्रति दिन) और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ९७२ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह (३२ रु. प्रति दिन) से कम खर्च करने वाले लोगो को गरीब बताया । इस समिती के अनुसार २०११–२०१२ में भारत मे गरीबो की जनसंख्या २९.५ प्रतिशत थी । सबसे गरीबी वाले राज्य छत्तीसगढ ४७.९ प्रतिशत, मणिपूर – ४६.७ प्रतिशत और ओडिशा – ४५.९ प्रतिशत है । सबसे कम गरीबो का अनुपात गोवा में है तथा गरीबों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार में है ।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के अनुसार सामान्य अवधि ३० दिन के भीतर सभी वस्तुओं पर खर्च तथा मिश्रित अवधि (३६५ दिन) में ५ अखाद्य वस्तुओं – वस्त्र, जूते – चप्पल, टिकाऊ वस्तुएँ, चिकित्सा और शिक्षा पर खर्च को गरीबी के सर्व्हेक्षण का आधार बनाया ।

इसके अनुसार भारत में गरीबी के आकडे निम्नानुसार है –

सर्व्हेक्षण वर्ष	भारत	ग्रामीण	शहरी
२००४–२००५	३७.२ %	४२.०० %	२५.०५ %
२००९–२०१०	२९.८ %	३३.०८ %	२०.०९ %
२०११–२०१२	२१.९५ %	२५.०७ %	१३.०७ %
वर्ष २०१८	कुल संख्या – ७,१३,५७,६१२		

स्त्रोत – ब्रुकिंग्स इंस्टिटयुट, विश्व बॅक, जुलाई २०१८

योजना आयोग द्वारा (नीति आयोग) जारी आकडो के अनुसार २००४–२००५ से लेकर २००९ – २०१० के दौरान देश में गरीबी ७ प्रतिशत घटी है और गरीबी रेखा अब ३२ रुपये प्रतिदिन से घटकर २८ रुपये ६५ पैसे प्रतिदिन हो गई है । मई २०१८ के आकडे लिए जाएँ तो, भारत में घोर दरिद्रता की स्थिती में रहनेवालो की संख्या ७.३० करोड है । आंतरराष्ट्रीय रुप से सुत्रसिध्द ब्रुकिंग्स संस्थान की रिपोर्ट यह बताती है । वर्ष २०१८ में विश्व के गरीबो की कुल अनुमानित संख्या ६४ करोड मानी जाती है । जिसका अर्थ है कि भारत में अब इसकी ११ प्रतिशत आबादी ही निवास करती है गरीबी की यह परिभाषा विश्व बॅक द्वारा वर्ष २०१५ में निश्चित की गयी थी चूकिं गरीबो की सबसे अधिक संख्या भारत में ही रहती है । इसीलिए

स्वाभाविक ही था कि विश्व का विशिष्ट ध्यान भारत पर ही होगा । यहॉ नाटकीय तेजी से गरीबो में गिरावट आयी और २०१०—२०१२ के अंतराल में बिलकुल निर्धनों की तादाद २७. करोड से घटाकर ७.३० करोड पर ला दी गयी । इस दर से वर्ष २०२२ तक भारत में गरीबी अपनी परिभाषा के अनुसार, लगभग खत्म हो चुकी होगी ।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष २००७ से २०१६ के बीच रिकॉर्ड २७.१० प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले है । भारत में गरीबी रेखा की परिभाषा तय करने का अधिकृत दायित्व योजना आयोग (नीति आयोग)को सौपा गया है । बहुआयामी गरीबी सूचकांक — २०१९ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड हयूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) ने जारी किया है । सूचकांक में भारत की गरीबी रेखा बेहतर हुई । भारत में २००६—२०१६ के बीच गरीबी से २७१ मिलियन लोग बाहर निकले है ।

निष्कर्ष :—

देश में गरीबों की संख्या के बारे में अलग—अलग अनुमान लगाये जाते है । विश्वबॅक के अनुसार भारत में २७ करोड लोग गरीब थे । तत्कालीन वित्तमंत्री स्व. अरुण जेटली के अनुसार देश में २५ करोड लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है । (वर्ष २००५ से २०१५—२०१६) इस दशक में २७ करोड लोगों को गरीबी की गर्त से बाहर लाया गया ।

भारत एक विकसनशील देश है फिर भी गरीबी एक व्यापक समस्यॉ बनी हुई है । इसे खत्म करने हेतू युध्द स्तर पर कार्य करने की जरुरत है । गरीबी उन्मुलन समाज और अर्थव्यवस्था की एक सतत और समावेती वृध्दि सुनिश्चित करेगा । सरकार द्वार उठाये जा रहे कदमों में हम सभी को गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में हर संभव सहयोग देना चाहिए । सरकारी प्रयासों से गरीबी को रेखा के नीचे जीवनयापन करनेवालों की संख्या घट रही है, किंतू गति धीमी है,

भारत में गरीबी के नीचे जीवनयापन करनेवाले नागरिकों की संख्या बहुत विशाल है । ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए यह एक चिंताजनक विषय है । सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न समितियों ने गरीबी की रेखा के अलग —अलग मापदंड बनाए है । मापदंड बदलने से समस्या नही बदलेली । ऑकडो को बदलने से सच्चाई नही बदलेगी ।

संदर्भ सूची :

१) इंटरप्राईजिंग मीडिया प्रा. लि. कलकत्ता, द पब्लिक एंजेडा पत्रिका – योजना योजना की गरीबी १६–३० जुन २०११, पृ. क्रं. ३२

२) धनकर प्रकाशन मेरठ – अर्थव्यवस्था अवलोकन 'भारत में गरीबी के ऑकडे, पृ. ४०, २० जून २०१२

३) योजना पत्रिका – योजना भवन नई दिल्ली – आबादी के लिए खाद्यान्न उपलब्धता – गौरव कुमार, पृ. ३३, जुलाई २०११

४) मनोरमा इयर बुक २०१९ मलयाला मनोरमा कंपनी, लिमीटेड, गरीबी और बरोजगारी, सचिन कुमार, पृ. ९३

५) मनोरमा इयर बुक २०१७ मलयाला मनोरमा कंपनी, लिमीटेड, आर्थिक वृध्दि : गरीबी की दूश्मन, अरुण जेटली, पृ. ४०४

६) दै. लोकमत दि. १५ डिसेबंर २०१९, विकास की परिभाषा बदले : एन. के. सिंह

७) https;//www.worldbank-org

८) https://britannica.com

९) https://www.google.com

१०) https://wikipedia.org

११) niti.gov.in